साहित्य में शिक्षा के प्रश्न और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

डॉ. नृत्य गोपाल

भारत सरकार की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' प्रस्तुत है। इसे 29 जुलाई 2020 को अंतरिक्ष विज्ञानी के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली शिक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसे प्रस्तावित करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा–''मुझे लगता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श वाला नवाचार का विमर्श है। इसमें लगभग सवा लाख पंचायत समितियों की सहभागिता रही है। सवा दो लाख सुझाव आए हैं।...हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अलग शिक्षा मंत्रालय दिया है। इसमें हमने नाम ही नहीं नीति भी बदली है। कार्य प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। इससे नया भारत बनाने में मदद मिलेगी।''[1]

7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात रखी। मोदी जी के कार्यक्रम का नाम Conclave on Transformational Reforms in Higher Education Under National Education Policy रखा गया था। इसमें बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि–''हमारे सामने सवाल था कि क्या हमारी नीति युवाओं को अपने सपने पूरा करने का मौका देती है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं को सक्षम बनाती है? नई शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से काम किया गया है। दुनिया में आज एक नई व्यवस्था खडी हो रही है, ऐसे में उसके हिसाब से एज्युकेशन सिस्टम में बदलाव जरूरी है, अब 10+2 को भी खत्म कर दिया गया है, हमें विद्यार्थी को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि वे अपनी जडों से जुडे रहें।''[2] आगे उन्होंने कहा था कि ''देश का एज्युकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आनेवाली पीढ़ी का फ्यूचर रेड्डी रखे। 'नई शिक्षा नीति 2020' 21वीं सदी के भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है।''[3]

नई शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव भारत को पहली बार शिक्षा मंत्रालय मिलना है। इससे पूर्व शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन थी। संभवतः मंतव्य यही रहा होगा कि शिक्षा मानव के विकास का संसाधन है। यों राज्य सरकारों में शिक्षा मंत्रालय आरंभ से हैं। इस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच बने आ रहे शिक्षा संबंधी पार्थक्य को समाप्त करना व्यवस्थागत रूप में उठाया गया सही कदम कहा जाएगा।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' का महत्त्व इस बात में भी है कि किसी बड़े भारतीय राजनीतिक दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा नीति लाने की बात की थी और उस पर अमल किया है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनावी मुद्दे प्रायः लोक लुभावन हुआ करते हैं, ऐसे में शिक्षा जैसा राष्ट्रीय हित का विषय जन सामान्य की चिंता के केंद्र में आया, इससे भारत की जनता में शिक्षा के महत्त्व को बल मिला है। भारत के विकास की दृष्टि से यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। संभव है 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' से बहुत बड़ा वोट बैंक भलेहि न बना हो पर राष्ट्रहित के विषय जन सामान्य के चिंतन में आएँगे तो देश के विकास को गति अवश्य मिलेगी।

'शिक्षा' और 'शिक्षा नीति' दो भिन्न प्रकार की अवधारणाएँ और प्रक्रियाएँ हैं। शिक्षा के महत्त्व और आवश्यकता पर चर्चाएँ मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ी हुई हैं। 'शिक्षा' पर कोई नीति, प्रतिबंध या व्यवस्था का स्वाभाविक प्रश्न दिखाई नहीं पडता। जिज्ञासा, प्राप्ति और अधिगम शिक्षा के मूलभूत तत्व कहे जा सकते हैं। शिक्षा विहीन जीवन को अभिशाप माना जाता रहा है।

शिक्षा नीति एक सरकारी दस्तावेज है। इसके प्रस्तावों के प्रति सरकार जिम्मेदार है। इनके क्रियान्वयन का दायित्व सरकार या सरकारों का है। संवैधानिक प्रावधानों के अधीन समाज की दशा एवं दिशा से नीति निर्माण का संकल्प आकार ग्रहण करता है। नीति प्रावधानों में भूत, वर्तमान और भविष्य का आकलन महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा नीति कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है इसमें न केवल विद्यार्थियों का हित जुड़ा होता है वरन् वैश्विक शिक्षा और समाज व्यवस्था में हमारी भूमिका भी तय होती है। कोई कारण तो होगा कि स्वतंत्र भारत में इस व्यवस्था पर नीतिगत निर्णय बहुत विलंब से लिए जा रहे हैं? 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' भारत की जनता के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नीति है। इसके समग्र क्रियान्वयन के लक्ष्य तय किए गए हैं। सभी को शिक्षा सुलभ हो यह संकल्प है। प्राथमिक स्तर पर इसके प्रभाव पूर्व की शिक्षा नीति में भी दिखाई पड़ते हैं। हम भारत को साक्षर बनाने में कई कदम आगे बढ़े हैं पर शिक्षित

करने में इतने आगे नहीं आए हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए हम विद्यार्थियों को सहेज नहीं पाते। नई शिक्षा नीति में बड़ा लक्ष्य है वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात Ggross Enrolment Ratio-GER को 100 प्रतिशत तक लाना। सरकार और प्रस्तोता तथ्य के रूप में कागजों में सुरक्षित रहेंगे; प्रभाव भारत की तस्वीर लिखेगा।

देश की शिक्षा नीति का संबंध देश की अर्थ व्यवस्था से भी है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। लंबे समय तक यह हिस्सेदारी 3 प्रतिशत के आसपास बनी रही है। बड़ी जनसंख्या वाले देश में इस हिस्सेदारी के अपने मायने हैं। निश्चित रूप में इससे शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढाँचागत सुधार संभव हो पाएगा। भवन के रूप में किसी विद्यालय का खड़ा होना एक बात है, पर वह शिक्षा नहीं है शिक्षा केंद्र है। शिक्षा केंद्र का अपना महत्त्व है पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भवन विहीन अर्थात् जंगल में या वृक्षों के नीचे भी भारत की शिक्षा व्यवस्था यशस्वी रही है। इसलिए नई शिक्षा नीति में आकलन सुधार का प्रावधान कहता है कि 'एनईपी 2020' में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता आधारित है, सीखने के साथ साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है, और उच्च स्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है।''[4] इसके लिए एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र 'परख' (समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का योगदान अविस्मरणीय है। वर्ष 1948 में आपकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। भारत में शिक्षा नीति के निर्धारण का यह महत्त्वपूर्ण पड़ाव था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21क में यह प्रावधान-''राज्य, छह से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।''[5] भारत की आधारभूत शिक्षा नीति का संकेत करता है। कोठारी आयोग की सिफारिशों पर 1968 में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव हुए। सन् 1986 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986' का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसकी एक विशेषता थी कि पूरे देश में एक समान शिक्षा तंत्र 10+2+3 की संरचना को अपनाया गया था। अब प्रस्तावित शिक्षा नीति में इसे 5+3+3+4 के रूप में लाया गया है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' का यह बड़ा बदलाव है। इसके क्रियान्वयन का मंतव्य और भी महत्त्वपूर्ण है जिसमें कहा गया है कि ''एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (एनसीपीएफईसीसीई) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा विकसित करेगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) मुहैया कराई जाएगी।''[6]

वर्ष 1986 से 2020 तक शिक्षा का क्षेत्र नितांत नीति विहीन रहा हो ऐसा नहीं है। पर, विधिवत् और व्यापक शिक्षा नीति जिसे कहा जा सके वह 2020 में प्रस्तावित हुई है। लगभग 3 दशक का यह अंतराल कम नहीं है। इसके राजनीतिक मंतव्य जो भी हों शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई बेहतर संकेत तो नहीं कहे जा सकते। अब जबकि नई शिक्षा नीति व्यापक विचार विमर्श के बाद प्राप्त हुई है तो आशा की जा सकती है कि भारत में शिक्षा के आधारभूत ढाँचे को वह ऊर्जा मिलेगी जिसकी इस क्षेत्र को बहुत आवश्यकता है।

साहित्य और शिक्षा : साहित्य और शिक्षा का संबंध अविच्छिन्न है। ऋग्वेद में जब वाक्सूक्त उद्धृत हुआ उसी के साथ साहित्य और शिक्षा का संबंध स्थापित हो गया। साहित्य और शिक्षा का एक रस संबंध इतना गहरा है कि उस पर चिंतन अथाह है। 20वीं शती के हिंदी साहित्य से कुछ चिंतन बिंदु उद्धृत किए जा रहे हैं जिनका सीधा संबंध नई शिक्षा नीति में बताए गए उद्देश्यों से है। यहाँ दो उदाहरण स्वतंत्रता पूर्व तथा दो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य से लिए जा रहे हैं।

'भारत भारती' 20वीं शती के आरंभ में लिखी गई वह काव्य कृति है जिसने अपने रचनाकाल में जितनी ख्याति प्राप्त की आज भी उसका महत्त्व उतना ही बना हुआ है। मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा रचित इस कृति में भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का वर्णन किया गया है। एक बड़े साहित्यकार की दृष्टि की व्यापकता इस कृति में दिखाई पडती है। सन् 1912-13 में प्रकाशित इस कृति में शिक्षा के प्रति जो प्रश्न गुप्त जी ने उठाए थे वे आज भी ज्यों के त्यों दिखाई पडते हैं। हाँ कुछ के उत्तर नई शिक्षा नीति 2020 में अवश्य देखे जा सकते हैं।

भारत का अतीत विद्यापूरित और गौरवशाली रहा है। इतिहास साक्षी है कि इस देश में ज्ञान की विभिन्न धाराएँ पूर्ण विकसित रूप में उपस्थित रही हैं। गुप्त जी लिखते हैं–

पांडित्य का इस देश में सब ओर पूर्ण विकास था,
बस, दुर्गुणों के ग्रहण में ही अज्ञता का वास था।
सब लोग तत्व ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ-
हाँ, व्याध भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ![7]

भारत का विद्याध्ययन भी एकांगी या एकमार्गी नहीं था। इसमें विद्याओं का वैविध्य था। गुप्त जी इस क्रम में लिखते हैं कि–

हम वेद, वाकोवाक्य विद्या, ब्रह्मविद्या विज्ञ थे,
नक्षत्र-विद्या, क्षत्र-विद्या, भूत-विद्याभिज्ञ थे।

निधि-नीति-विद्या, राशि-विद्या, पितृ- विद्या में बढ़े,
सर्पादि-विद्या, देव-विद्या, दैव-विद्या थे पढे।[8]

भारत में विद्याध्ययन बहुमुखी था। दिग्दिगांत का ज्ञान हमारे पूर्वजों को था। संसार का संपूर्ण ज्ञान हमारे पास ही था ऐसा तो नहीं है, पर हम पर्याप्त ज्ञान संपन्न थे। दुनिया हमारे पास शिक्षा के लिए आ रही थी। पर, यह अतीत की बात थी। भारत भारती के वर्तमान खण्ड में गुप्त जी जिस शिक्षा व्यवस्था की बात कह रहे थे वह अभी भी बनी हुई है। नई शिक्षा नीति उससे बाहर निकलने का प्रयास करती दिखाई पड़ती है। लगता है जैसे जो प्रश्न गुप्त जी ने उठाए थे उनका समाधान इस शिक्षा नीति में मिल रहा है। गुप्त जी लिखते हैं कि आज शिक्षा का अर्थ नौकरी हो गया है। समाज का जो वर्ग साधन संपन्न है वह इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि इस शिक्षा से मात्र नौकरी मिलती है इसलिए हमें पढ़कर क्या करना है। दूसरा वर्ग है जो नौकरी प्राप्त करने तक ही पढ़ना चाहता है। यदि कोई पिता अपने पुत्र को शिक्षा के कुछ सिद्धांत सिखाए तो रईस सपूत की माता कहती है कि इसे पढ़कर क्या करना है?

श्रीमान् शिक्षा दें उन्हें तो श्रीमती कहती वहीं–
''घेरो न लल्ला को हमारे, नौकरी करनी नहीं।''
शिक्षे! तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी,
लो मूर्खते! जीती रहो, रक्षक तुम्हारे हैं धनी।[9]

नई शिक्षा नीति 2020 जब उद्यमशील और आत्मनिर्भर शिक्षा की बात करती है तो लगता है कि हम शिक्षा के क्षुद्र उद्देश्य (नौकरी) से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। नए भारत के लिए यह महत्त्वपूर्ण बदलाव होगा।

1947 से पूर्व की भारतीय शिक्षा का एक चित्र मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी 'बड़े भाई साहब' में अंकित किया है। इसका रचनाकाल सन् 1930 के आसपास का होगा। बड़ा भाई नौवीं कक्षा का छात्र और छोटा भाई पाँचवीं कक्षा में पढ़ता है। बड़ा भाई दिन रात किताबों में उलझा रहे और छोटा खेलकूद के साथ व्यवहार बुद्धि से काम ले। इम्तिहान का परिणाम किताब के विरुद्ध और व्यवहार के पक्ष में खड़ा दिखाई पड़ा। बड़े भाई ने कहा–''महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो।''[10] भारतीय शिक्षा पद्धति में किताब का महत्त्व बढ़ गया है। व्यवहार ज्ञान हमसे दूर हो चला है। प्रेमचंद गणित और इतिहास की शिक्षा के माध्यम से लिखते हैं–''जामैट्री तो बस, खुदा ही पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल-भात-रोटी खाई या भात-दाल-रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लडके अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोडा है और आखिर इन बे सिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा?''[11] इतिहास शिक्षा के स्वरूप पर प्रेमचंद लिखते हैं कि–''बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। आठ आठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवाँ लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट। सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी। हो किस खयाल में। दरजनों तो जेम्स हुए हैं, दरजनों विलियम, कोडियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है।''[12]

भारत में मैकाले की शिक्षा पद्धति की जो आलोचना होती है उसमें यह व्यवस्था थी। जहाँ रटंत को ही शिक्षा कह छोडा था। नई शिक्षा नीति 2020 को प्रस्तुत करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा था कि–''मेरा मानना है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हम भारत को गुणवत्ता परक, नवाचार युक्त, प्रौद्योगिकी युक्त और भारत केंद्रित शिक्षा दे पाने में सफल होंगे।''[13] इस शिक्षा नीति के स्कूली शिक्षा भाग में स्पष्ट कहा गया है कि ''एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटिज मेन कैरिकुलम में शामिल होंगे।''[14] साथ ही यह प्रावधान भी है कि–''रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स शामिल होंगे।''[15] लगता है प्रेमचंद ने दो बालकों के माध्यम से शिक्षा के जिस स्वरूप को समाज के सामने लाने का प्रयास किया था नई शिक्षा नीति में उन दोनों को सम्मान देने का प्रावधान हुआ है।

शिक्षा का बजट अब सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत किया गया है। इसका सीधा सा असर शिक्षा के आधारभूत ढाँचे के विकास पर पड़ेगा। स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था पर विचार करते हुए जनकवि नागार्जुन ने कविता लिखी थी 'मास्टर'। इस कविता में दुखरन मास्टर की परिस्थितियों और संवेदनाओं के माध्यम से स्कूलों की दशा, शिक्षा नीति का खोखलापन और प्रजातंत्र में दिखावे की प्रवृत्ति पर तीखा व्यंग्य किया गया है। यहाँ स्वतंत्र भारत का शिक्षक, विद्यालय, विद्यार्थी और शिक्षा मंत्री एक साथ मौजूद हैं और बाबा नागार्जुन इस दुर्दशा की शिनाख्त इस कविता में करते हैं। नागार्जुन विद्यालय की दशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं–

घुन-खाए शहतीरों पर की बाराखडी विधाता बाँचे
फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिसतुइया नाँचे
बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में पाँच तमाचे
दुखरन मास्टर गढते रहते किसी तरह आदम के साँचे।[16]

दुखरन मास्टर विद्यार्थियों के लिए विधाता है। पर उसका स्वयं का स्वरूप क्या है? जनकवि ने उसकी काया का भी चित्रण किया है–

खिचड़ी बाल, साँवली सूरत दुखरन प्राइमरी के मास्टर
लपके लपके बढ़े आ रहे मैदानी हाते के भीतर''[17]

सूबे के शिक्षा मंत्री इसी क्षेत्र से हैं। मास्टर जी के पुराने मित्र हैं। दुखरन को लगता है शिक्षा व्यवस्था का वर्णन उनसे तो किया ही जा सकता है। वे मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। पर, उनके दरवाजे पर एक शिक्षक के साथ जो व्यवहार हुआ उससे यह विधाता बहुत दुखी हुआ। वर्णन करते हैं–

फाटक पर पहुँचे तो देखा, डटे हुए थे दो नेपाली
हाथों में संगीन सँभाले, लटक रही थी निजी भुजाली
''कहाँ जाएगा?'' वे गुर्राए, आँखों में उतराई लाली
दुखरन का दिल दुखी हुआ, सुन सूखा तू तू सूखी गाली
मास्टर बोले, ''यों मत कहना, पढा लिखा हूँ, मैं हूँ शिक्षक
तुम भी हो जनता के सेवक, मैं भी हूँ जनता का सेवक''
फिर तो वे धकियाकर बोले ''भाग भाग, जा मत कर बक बक
हम फौजी हैं, नहीं समझते क्या होता है सिच्चक सेपक।''[18]

दुखरन दुखी होते हैं। यह शिक्षक समाज का साझा दुख है। पर, इसे कहा किससे जाए? इसका समाधान कहाँ है? दुखरन ने कलम उठाई। यही उसका हथियार है। मंत्री जी के नाम पत्र लिख दिया। जो दुःख मिलकर नहीं कह पाया वह पत्र में व्यक्त कर डाला।

आदर्शों की छौंक मारकर अजी आपने हमें सुधारा
उपदेशों की धुआँधार में अकुलाता शिक्षक बेचारा
अजी आपको लगता होगा सुखमय यह भूमंडल सारा।
लिखा अंत में ''ध्यान दीजिए, बहुत दिनों से मिला न वेतन
किससे कहूँ, दिखाई पडते कहीं नहीं अब वे नेता-गण
पिछली दफे किया था हमने पटने में जा-जा के अनसन
स्वयं अर्थ-मंत्री जी निकले, वे दे गए हमें आश्वासन
और क्या लिखूँ, इन देहाती स्कूलों पर भी दया कीजिए
दीन हीन छात्रों-गुरुओं की कुछ भी तो सुध आप लीजिए
हटे मिटे यह निपट जहालत, प्रभु ग्रामीणों पर पसीजिए
कई फंड हैं उनमें से अब हमको वाजिब एड दीजिए।''[19]

भारत स्वतंत्र हुआ। रातों रात चाँद तारे धरती पर आ जाएँ ऐसा तो नहीं था। पर, सद्प्रयास का उपक्रम हमारे हाथ में था हम वह नहीं कर पाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उस सद्प्रयास का आभास करा रही है। यहाँ विद्यालय, विद्यार्थी, अभिवावक और शिक्षक की दशा सुधारने का प्रावधान दिखाई पड रहा है। यहाँ व्यवस्था की गई है कि शिक्षक पेशेवर मानकों का पालन करें। पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उनकी भर्ती की जाएगी। योग्यता आधारित पदोन्नति होगी। समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन होगा जिसके माध्यम से वे शैक्षणिक प्रशासक भी बन पाएँगे।

अस्पष्ट शिक्षा नीति के दंश ने भारत की शिक्षा व्यवस्था का दम फुला दिया है। साहित्य में अनेकानेक दृष्टियों से इसका विवेचन विश्लेषण हुआ है। सभी की चर्चा करना न तो हमारे लिए संभव है और न ही अपेक्षित। एक और कृति के उल्लेख के साथ इस चर्चा को अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर किया जा रहा है। कृति है श्रीलाल शुक्ल की कालजयी रचना 'राग दरबारी'। हिंदी साहित्य का प्रत्येक अध्येता इस रचना के प्रभाव से परिचित है। इसमें ग्रामीण भारत का सजीव चित्रण सभी को अपने भीतर झांकने के लिए विवश करता है। इस कृति में भारत की झाँकी है, जहाँ बड़े पर्दे के पीछे शिक्षा दर्शन केंद्र में दिखाई पडता है। 1968 में प्रकाशित रागदरबारी उपन्यास भारत की शिक्षा व्यवस्था का चित्र कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करता है–''वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पडी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है।''[20] सनद रहे कि राग दरबारी उपन्यास उसी वर्ष प्रकाशित होता है जिस वर्ष कोठारी आयोग शिक्षा में सुधार के सुझाव देता है। शिवपाल गंज का छंगामल इंटर कॉलेज भारत की शिक्षा व्यवस्था को तार तार करता दिखाई पडता है। लगातार प्राईवेट क्षेत्र की ओर बढती शिक्षा व्यवस्था किस ओर जाएगी इसको राग दरबारी के वैद्य जी से सीखना होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध की दुर्गति पर व्यंग्य करते हुए रिसर्च स्कॉलर रंगनाथ के माध्यम से लेखक जो कहता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। जो इस शिक्षा नीति में दिखाई पडती है। ट्रक ड्राइवर रंगनाथ से पूछता है–''शिरिमान जी, आजकल क्या कर रहे हैं? इस पर वह जवाब देता है कि घास खोद रहा हूँ। ड्राइवर कहता है–''क्या बात कही है, जरा खुलासा समझाइए।'' रंगनाथ कहता है–''कहा तो, घास खोद रहा हूँ। इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। परसाल एम.ए. किया था। इस साल से रिसर्च शुरू की है।''[21] शिक्षा के क्षेत्र की महान उपलब्धि का उल्लेख करते हुए उपन्यासकार कहता है–''शिक्षा के क्षेत्र में पिछली शताब्दी की यह असाधारण उपलब्धि है कि हम इतनी जल्दी जान गए कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है।''[22]

शिक्षा पद्धति खराब है तो ठीक भी हो जाएगी। उसका एक ही माध्यम है ईमानदारी से खराबी को स्वीकार करने और उसे दूर करने की। नई शिक्षा नीति इसे दूर करने में सक्षम है। प्रथम दृष्टया यही दिखाई पड़ता है। हम भारत के सभी नागरिक कितनी ईमानदार कोशिश करेंगे यह देखना है। लोकनीति के प्रसिद्ध कवि वृंद ने लिखा था–

विद्या धन उद्यम बिना, कहौ सु पावै कौन।
बिना डुलाए न मिलै, ज्यौं पंखा कौ पौन।।[23]

संदर्भ :

1. श्री रमेश पोखरियाल निशंक, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, प्रेस कांफ्रेस अंश 29.7.2020
2. श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार का उद्बोधन, 7.8.2020

3. श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार का उद्‌बोधन, 7.8.2020
4. नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा, ई वर्जन
5. भारत का संविधान एक परिचय, डॉ. दुर्गादास बसु पृ.180
6. नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा, ई वर्जन
7. मैथिलीशरण गुप्त, भारत भारती, अतीत खण्ड, 75
8. मैथिलीशरण गुप्त, भारत भारती, अतीत खण्ड, 78
9. मैथिलीशरण गुप्त, भारत भारती, वर्तमान खण्ड, 125
10. प्रेमचंद, कहानी : बड़े भाई साहब
11. प्रेमचंद, कहानी : बड़े भाई साहब
12. प्रेमचंद, कहानी : बड़े भाई साहब
13. श्री रमेश पोखरियाल निशंक, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, प्रेस कांफ्रेंस अंश 29.7.2020
14. नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा, ई वर्जन
15. नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा, ई वर्जन
16. नागार्जुन, कविता : मास्टर
17. नागार्जुन, कविता : मास्टर
18. नागार्जुन, कविता : मास्टर
19. नागार्जुन, कविता : मास्टर
20. श्री लाल शुक्ल, राग दरबारी, पृ.10
21. श्री लाल शुक्ल, राग दरबारी, पृ.7
22. श्री लाल शुक्ल, राग दरबारी, पृ.157
23. कवि वृंद, वृंद सतसई

हिंदी विभाग, हंसराज कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली